बिन संस्कार नहीं सहकार

बिना सहकार नहीं उद्धार

छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार

वर्ष- 23 अंक - 9 अगस्त 2026 प्रथम पाक्षिक RNI NO. CHHHIN/2012/45105 प्रकाशन तिथि 15 अगस्त पृष्ठ-12 मूल्य 2000/- वार्षिक

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने बताया 2047 तक देश का लक्ष्य

'रक्षा शक्ति' सात धाराओं में से एक, सुदर्शन चक्र मजबूत स्वदेशी सुरक्षा कवच : पीएम मोदी

नई दिल्ली। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने एआई, यूथ स्केलिंग, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट जैसे बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 2035 तक देश की रक्षा और सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 'मिशन सुदर्शन चक्र' की प्रगति का जिक्र किया। इसके तहत सामरिक और नागरिक ठिकानों को एक मजबूत स्वदेशी सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'रक्षा शक्ति' को शक्ति की सात धाराओं में से एक बताया। उन्होंने कहा यह 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की कुंजी है। 15 अगस्त, 2026 को दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया और भारत के आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में युवाओं से समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका संभालने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने 13वें संबोधन में देश से नक्सलवाद के खात्मे का उल्लेख किया और कहा कि चुनौती को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए तथा सतर्क रहना होगा क्योंकि 'हथियारी नक्सल भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन 'दिमागी नक्सली' अब भी मौके की तलाश में हैं। अपने 75 मिनट के संबोधन में मोदी ने 'शक्ति की सप्तधारा' का उल्लेख किया और कहा कि विनिर्माण शक्ति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर वो शक्तियां हैं जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की ताकि उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा, हर मां-बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं हैं। इन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की हम चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर से यह ऐलान भी किया कि आने वाले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को एआई कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने में समर्थ हो।

खेल के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज

मोदी ने 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत को मजबूत दावेदार बताते हुए कहा कि इस बड़े आयोजन में देश की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए पांच से 15 वर्ष की आयु तक के संभावित खिलाडियों की पहचान करने के वास्ते देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया जाएगा।

'दिमागी नक्सल' पर किया अलर्ट

पीएम मोदी ने नक्सलवाद को खत्म करने में अपनी सरकार की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा, जंगलों में 'हथियारी नक्सल के खिलाफ सफलता मिली है, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। उनका कहना था कि ऐसे तत्व हिंसा और अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं।

ऐसी घोषणाएं भी

- एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी
- 1-2 साल के अंदर 7-8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किए जाने की घोषणा
- सिविल डिफेंस में सुधार करने की भी घोषणा की
- गांवों और शहरों में बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान
- भारत ने 2047 तक 100 जीडब्ल्यू परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक पुनर्गठन और नए प्रयोगों पर जोर : सौरभ शर्मा

- जिला सहकारी संघों के पुनर्गठन, चुनावी पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और डिजिटल सहकारिता को बढ़ावा देने पर बनी कार्ययोजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारी आंदोलन में व्यापक पुनर्गठन और नए प्रयोगों की घोषणा करते हुए राज्य सहकारी बोर्ड तथा संबंधित जिला संघों ने हालिया बैठक में कई निर्णायक कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की सक्रियता, पारदर्शिता और आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों में सभी जिला सहकारी संघों का सुदृढ़ीकरण और उनका पुनर्गठन शामिल है ताकि सदस्यों तक सेवाएँ तेज़ और प्रभावी ढंग से पहुँच सकें। इस बड़े पुनर्गठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि बिलासपुर जिला संघ को परिसीमन प्रक्रिया के बाद अलग कर दिया गया है, जिससे बिलासपुर का प्रशासनिक दायित्व नए सीमांकन के अनुरूप सीमित होगा और उसके पड़ोसी जिलों को भी बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। यही नहीं, महासमुंद जिला संघ में जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिससे वहां स्थानीय समुदायों की भागीदारी और स्व-नियमन में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए नए नियम और निगरानी व्यवस्था प्रस्तावित

बैठक में सहकारी संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया पर जोर दिया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि छत्तीसगढ़ में सहकारिता को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है। राज्य सहकारी बोर्ड ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रियाएँ निर्धारित समय पर कराई जाएँगी तथा पहले से बनाए गए चुनावी नियमों में आवश्यक संशोधन कर पात्रता, नामांकन और मतगणना को और अधिक पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में चुनाव शिथिल रहे या विवादों से घिरे रहे हैं, वहां विशेष निगरानी टीम भेजी जाएगी और आवश्यकता पडने़ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या अन्य तकनीकी सहायता का प्रयोग कराया जाएगा ताकि मतदान की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय अनुशासन, ऋण वसूली और ऑडिट व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

बैठक के एजेंडे में बोर्ड के विषयों का एक विस्तृत समूह भी था – वित्तीय अनुशासन, ऋण वसुली नीतियाँ, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अपनाने, और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल मुख्य बिंदु रहे। विशेषकर वित्तीय अनुशासन पर यह निर्णय हुआ कि सभी राज्य सहकारी संघों को समय-समय पर ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए और जिन संघों की वित्तीय स्थिति कमजोर पाई जाएगी, उन्हें सुधार योजना देना अनिवार्य होगा। ऋण वितरण में सदस्य-हित और क्षमतानुसार ऋण नीति अपनाने का निर्देश दिया गया ताकि बाउंस बैक की संभावना घटे और ग्रामीण स्तर पर ऊँचे ब्याज या गैरकानूनी उधारी का दुष्प्रभाव रोका जा सके। बोर्ड ने यह भी प्रस्ताव रखा कि राज्य और जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाएँ जो प्रबंधन, लेखा, कस्टमर सर्विस और तकनीकी बदलाव पर कर्मचारियों व प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करें।

डिजिटल सहकारिता को बढ़ावा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए नया प्लेटफॉर्म प्रस्तावित

नवोन्मेष और डिजिटलरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए बोर्ड ने सहकारी OTT (Over-The-Top) सेवा शुरू करने का प्रस्ताव मान्यता दी है। यह सहकारी OTT प्लेटफ़ॉर्म सदस्यों तक प्रशिक्षण सामग्री, कानूनी और नियामक मार्गदर्शन, कृषि व उद्यमिता की जानकारी, बाज़ार-सम्बंधी वीडियो और लाइव-प्रशिक्षण सत्र पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। OTT का लक्ष्य विशेषकर युवा सदस्यों, छोटे उद्यमियों और स्व-रोजग़ार से जुड़े लोगों को आधुनिक डिजिटल टूल्स से जोडऩा है ताकि वे सहकारी फ्रेमवर्क के माध्यम से बेहतर उत्पादन, विपणन और वित्तीय प्रबंधन कर सकें। बोर्ड ने तकनीकी एग्रीग्रेटर पैनल बनाने का निर्णय लिया है जो स्थानीय भाषा व स्थानीय कनेक्ट के अनुसार सामग्री तैयार करेगा तथा OTT में सदस्यता मोड्यूल, लाइव चैट-सहायता और FQ सेक्शन जैसे सुविधाएँ शामिल रहेंगे।

सरल भाषा में सहकारी नियमों की पुस्तिकाएं होंगी प्रकाशित

संचार और शिक्षा बढ़ाने के लिहाज़ से छोटे छोटे सूचनात्मक नियमों की पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी स्वीकृत किया गया। इन पुस्तिकाओं में सहकारी बायलॉज, सदस्यता प्रक्रिया, वोटिंग का तरीका, ऋण लेने का सरल मार्गदर्शन, हितधारकों के अधिकार व कर्तव्य, और ग्राम स्तर पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में जानकारी होगी। बोर्ड ने निर्देश दिया कि ये पुस्तिकाएँ स्थानीय भाषाओं तथा सरल चित्रों के साथ छपी जाएँ ताकि नजरअंदाज़ होने वाले सदस्यों तक भी ये सुलभ हों। पुस्तिकाओं का वितरण स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों और जिला कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा और स्कूलों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान भी इन्हें वितरित किया जाएगा।

शेष पेज 07 पर...................

सहकारी संघ की समीक्षा बैठक : प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ की 7 जुलाई 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में संघ की विभिन्न गतिविधियों तथा पूर्व समीक्षा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। बैठक में प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण, अभिदाय-अंशदान की वसूली, छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार के प्रसार तथा लेखा-अंकेक्षण से संबंधित विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

वित्तीय प्रबंधन एवं अग्रिम राशि के समायोजन की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2026-27 के मई से जुलाई 2026 तक के आय-व्यय पत्रकों की समीक्षा के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं जीएसटी रिटर्न की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए गए कार्यालयीन एवं अन्य अग्रिमों का निर्धारित समय-सीमा में समायोजन करने के निर्देश दिए गए।

सदस्य संस्थाओं से बकाया अभिदाय-अंशदान की होगी वसूली

संघ की सदस्य संस्थाओं से विगत वर्षों से बकाया अभिदाय-अंशदान राशि वसूली की समीक्षा की गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से प्राप्त वित्तीय पत्रकों के आधार पर वास्तविक बकाया राशि की जानकारी तैयार कर स्थिति विवरण में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। संबंधित सहकारी संस्थाओं को पुनः स्मरण पत्र जारी करने तथा बकाया अभिदाय-अंशदान की वसूली के लिए नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करने पर भी जोर दिया गया।

'छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार' के प्रसार एवं ग्राहक संख्या बढ़ाने पर जोर

बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी समाचार के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने, समाचार संकलन एवं विज्ञापन प्राप्त करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संघ मुख्यालय रायपुर एवं सहकारी प्रशिक्षण केंद्र रायपुर के सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह एक नया ग्राहक बनाने का लक्ष्य दिया गया। सहकारी संस्थाओं से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए संपर्क करने तथा 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से समाचार प्राप्त करने तथा जिला सहकारी संघों से भी समाचार संकलित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।

सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बनाया जाएगा प्रभावी

शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सहकार से समृद्धि विषय को प्रशिक्षण में शामिल करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षणार्थियों को संघ की ओर से आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए नवीन प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।

टेली एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रगति की समीक्षा

पिछले तीन माह में टेली एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में की गई प्रविष्टियों एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रविष्टियों के परीक्षण एवं मिलान की कार्यवाही में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर 15 दिवस के भीतर सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक में राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा, प्रबंध संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी ध्रुव एवं संघ के अधिकारी व कर्मचारी गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

लंबित अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण जल्द हो

संघ के लंबित अंकेक्षणों की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंकेक्षण आपत्तियों एवं सुझावों के निराकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की आपत्तियों के निराकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य निर्धारित समयावधि में आयुक्त सहकारिता, छत्तीसगढ़ को पालन प्रतिवेदन प्रेषित करना है। समीक्षा बैठक में संघ के लंबित कार्यों का समय-सीमा में निराकरण, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने तथा सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

'सहकार से समृद्धि' में लैम्पस सहकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

■ भानपुरी लैम्पस के आश्रित ग्राम चमिया में सहकारी एवं कृषक प्रशिक्षण संपन्न

■ नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग की दी गई जानकारी

भानपुरी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वाववधान में संचालित संभागीय कार्यालय जगदलपुर एवं इफ्को के क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत भानपुरी लैम्पस के आश्रित ग्राम चमिया के पंचायत भवन में सहकारी एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने सहकारिता के अर्थ, महत्व एवं सिद्धांतों की जानकारी देते हुए लैम्पस द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विशेष रूप से वित्तीय सेवा, विपणन एवं प्रसंस्करण सेवा, उपभोक्ता सेवा तथा उत्पादन वृद्धि में सहायक सेवाओं की जानकारी दी।

गो पालन, बकरी पालन योजनाओं की दी गई जानकारी

उन्होंने कहा कि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में लैम्पस सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कृषक बंधुओं को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत फसल ऋण के साथ-साथ गोपालन, बकरी पालन एवं मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी लैम्पस के माध्यम से ऋण प्राप्त कर आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया।

कृषि क्षेत्र में इफ्को का यसेगदान समझाया गया

इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी श्री लाल बहादुर सिंह एवं सहायक फील्ड असिस्टेंट श्री वैभव पांडे ने इफ्को की गतिविधियों एवं कृषि क्षेत्र में उसके योगदान की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एवं कंसोटिया जैसे जैविक/कृषि उत्पादों के विक्रय, उपयोग एवं प्रयोग विधि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती की ओर बढ़ने तथा वर्ष 2047 तक विकसित कृषि की दिशा में अपनी मृदा को स्वस्थ एवं टिकाऊ कृषि के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रेरित किया।

ऋण सेवाओं के बारे में दी गई जानकारी

लैम्पस भानपुरी के प्रबंधक श्री प्रफुल्ल पांडे ने किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत उपलब्ध ऋण सेवाओं एवं लैम्पस द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों एवं कृषकों को लैम्पस की सदस्यता ग्रहण कर सहकारी व्यवस्था से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम पंचायत चमिया के पंचायत प्रतिनिधियों, लैम्पस भानपुरी के अधिकारी-कर्मचारियों तथा संघ के श्री रोमांचल पाणिग्राही का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रशिक्षण में उपस्थित कृषक बंधुओं ने सहकारिता एवं कृषि संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त की।

चिरायु योजना से बाल मधुमेह से जूझ रही 11 वर्षीय बच्ची को मिला निःशुल्क उपचार

रायपुर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की चिरायु योजना ऐसे बच्चों के लिए आशा की किरण बन रही है, जो जन्मजात बीमारियों या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। समय पर पहचान, विशेषज्ञ उपचार और पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से यह योजना बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से समय पर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार उपलब्ध होने से न केवल बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर उपचार का बोझ भी कम हो रहा है। मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम नारायणपुर निवासी 11 वर्षीय किनामिका साहू के लिए भी चिरायु योजना ऐसी ही उम्मीद की किरण बनी है। किनामिका बाल मधुमेह से पीड़ित है और उसका उपचार पूर्व में बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उपचार एवं आवश्यक दवाइयों पर परिवार को प्रतिमाह लगभग 10 से 12 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह खर्च लगातार चुनौती बन रहा था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने बताया कि जांच के दौरान चिरायु टीम को बच्ची के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिली। इसके पश्चात टीम ने बच्ची को जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मधु ध्रुव से स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

पंडरीपानी में ग्रामीण महिलाओं को दिया गया सहकारी प्रशिक्षण

■ सहकारिता से रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसरों की दी जानकारी

पंडरीपानी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के तत्वावधान में तथा प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा के मार्गदर्शन में 8 अगस्त को पंडरीपानी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत एवं लाभ के साथ-साथ सहकारिता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को नई सहकारी समिति के गठन एवं पंजीयन की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में महिलाओं को सामूहिक रूप से कार्य करते हुए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनने के लिए सहकारिता को प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारी श्रीमती हेमवती सोनी ने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना, सुकन्या योजना, महतारी मातृत्व योजना, दत्तक पुत्री योजना, सबला योजना, महतारी वंदन योजना एवं सक्षम योजना सहित अन्य योजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ के संबंध में महिलाओं को अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं ने सहकारिता एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त की तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री सुदन राम मौर्य का विशेष योगदान रहा।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

■ **नाबार्ड निरीक्षण, शाखा विस्तार एवं गबन-धोखाधड़ी मामलों की निगरानी सहित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा**

जगदलपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के संचालक मंडल की महत्वपूर्ण बैठक बैंक के प्रधान कार्यालय, जगदलपुर में आयोजित हुई। बैठक में बैंक के सुचारु संचालन, संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वित्तीय अनुशासन एवं बैंकिंग सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

गबन-धोखाधड़ी मामलों की नियमित निगरानी

बैंक में गबन एवं धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा के विषय को बैठक में गंभीरता से लिया गया। ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति के पुनर्गठन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैंक में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी चर्चा हुई।

बैंक संचालन को प्रभावी बनाने पर जोर

संचालक मंडल की बैठक में बैंक की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्णयों एवं आगामी कार्यवाही पर चर्चा की गई। साथ ही बैंक की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने तथा सदस्यों एवं ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास करने पर बल दिया गया।

नाबार्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर हुई चर्चा

बैठक में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की स्थिति को लेकर किए गए निरीक्षण के संबंध में चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान सामने आए विभिन्न बिंदुओं, सुझावों तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही पर संचालक मंडल द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बैंक की कार्यप्रणाली को नियामकीय मानकों के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया।

शाखाओं के विस्तार एवं पुनर्गठन पर विचार

बैठक में बैंक की आवश्यकता एवं ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए *नई शाखाएं खोलने, संचालित शाखाओं को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने, शाखाओं के संविलियन तथा आवश्यकता के अनुरूप शाखाओं को बंद करने से संबंधित नियमित नीति के अनुमोदन के विषय पर भी चर्चा की गई। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण एवं सहकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप करने पर विशेष जोर दिया गया।

ये हुए सममानित

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री सुरेश कुमार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बास्तानार; द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली कु. पूनम मौर्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चोकर तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले श्री प्रदीप बंजारे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चोकर को सम्मानित किया गया।

निबंध प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों का सम्मान

बैठक के पश्चात सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं प्रोत्साहन राशि* प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इन विषयों पर रखे विचार

विद्यार्थियों ने 'गांव के विकास में सहकारिता की भूमिका' एवं 'एक के लिए सब, सबके लिए एक' जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उनके विचारों एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उपस्थित अतिथियों ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

बैठक में इनकी रही मौजूदगी

बैठक में बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप, उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास मिश्रा, नाबार्ड प्रतिनिधि श्री अभिजीत देवरी, उप आयुक्त डॉ. ऊषा ध्रुव, उप संचालक कृषि श्री राजीव श्रीवास्तव, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रतीक चिखलीकर, विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री धर्मपाल केरकेट्टा, उप महाप्रबंधक कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड श्री प्रियब्रत साहू, सहायक महाप्रबंधक श्री मयंक जैन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंवर सिंह ध्रुव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विष्णु सरकार ने बढ़ाया किसानों का मान खेती किसानी को मिला नया संबल

■ **छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति परंपरा व आस्था से जुड़ा है हरेली तिहार**

रायपुर। प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गांव, गरीब और किसान सरकार की पहली प्राथमिकता में हैं। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की इन ढाई साल के अवधि में किसानों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों से खेती किसानी को नया संबल मिला है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्यौहार परंपरागत् रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती-किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्यौहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है।

छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति परंपरा व आस्था से जुड़ा है हरेली तिहार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदीकर न सिर्फ किसानों को मान बढ़ाया, बल्कि किसानों को उन्नति की ओर ले जाने में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। साथ ही किसानों के खाते में रमन सरकार के पिछले दो वर्ष का बकाया धान के बोनस 3716.38 करोड़ रूपए अंतरित कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत गांवों में बसता है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का व्यापार, उद्योग बढ़ेगा। परंपरा के अनुसार वर्षों से छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले बढ़ई के घर में गेड़ी का ऑर्डर रहता था और बच्चों की जिद पर अभिभावक जैसे-तैसे गेड़ी भी बनाया करते थे। हरेली तिहार के दिन सुबह से तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं और खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को साफकर घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं की साथ पूजा करते हैं। गांवों के गुड़ी में ठाकुरदेव की पूजा की जाती है। हरेली पर्व के दिन पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधि युक्त आटे की लोंदी खिलाई जाती है। गांव में यादव समाज के लोग वनांचल जाकर कंदमूल लाकर हरेली के दिन किसानों को पशुओं के लिए वनौषधि उपलब्ध कराते हैं। गांव के सहाड़ादेव अथवा ठाकुरदेव के पास यादव समाज के लोग जंगल से लाई गई जड़ी-बूटी उबाल कर किसानों को देते हैं। इसके बदले किसानों द्वारा चावल, दाल आदि उपहार में यादवों को भेंट करने की परंपरा रही हैं।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओड़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती-किसानी का कार्य लगभग हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धोकर, धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ का चीला भोग लगाया जाता है। गांव के ठाकुर देव की पूजा की जाती है और उनको नारियल अर्पण किया जाता है। हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है।

सहकारी समिति का पंजीयन : भरोसे से पहचान तक की पूरी यात्रा

विशेष रिपोर्ट : सहकारिता के माध्यम से बदलती गाँवों की तस्वीर

जब तक हर किसान अकेले 'मैं' की भाषा में सोचता रहा, तब तक फसल का सही दाम, महँगे बीज-खाद और साहूकारी ब्याज जैसी समस्याएँ जस की तस बनी रहीं। पर जिस दिन गाँव के इन्हीं बिखरे स्वरों ने 'हम' की भाषा अपनाई, उसी दिन से हालात बदलने की कहानी शुरू हुई। सहकारी समिति का पंजीयन दरअसल इसी 'मैं' से 'हम' तक की यात्रा को कानूनी और संस्थागत पहचान देने का नाम है।

एकता की ताकत – गठरी वाली मिसाल

गाँव के एक बुजुर्ग शिक्षक ने एक बार यह बात बड़े रोचक ढंग से समझाई थी। उन्होंने लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर उठाया, पहले एक-एक लकड़ी अलग करके आसानी से तोड़ दी, फिर उन्हीं लकड़ियों को साथ बाँधकर गाँव के सबसे ताकतवर युवक को तोडने के लिए दिया। पूरा ज़ोर लगाने के बाद भी गट्ठर नहीं टूटा।

अकेले हम कमज़ोर हैं, पर साथ आने पर हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच को स्थायी पहचान देने का नाम है – सहकारी समिति का पंजीयन।

यही सहकारिता का मूल सिद्धांत है – व्यक्तिगत लाभ की सोच से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता देना। जिस दिन लोग इस भावना के साथ एकजुट होते हैं, उसी दिन सहकारिता का असल जन्म होता है; पंजीयन तो उसे कानूनी पहचान देने वाला औपचारिक कदम भर है।

पात्रता और तैयारी – पहला कदम कहाँ से शुरू हो

किसी भी सहकारी समिति की नींव एक साझा उद्देश्य से पड़ती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि केवल किसान ही आगे आएँ – महिलाएँ, युवा, बुनकर, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, वनोपज संग्राहक, उपभोक्ता और छोटे व्यापारी, कोई भी समान आवश्यकता और साझा हित रखने वाला समूह सहकारी समिति बना सकता है। शुरुआत में गाँव या समूह स्तर पर बैठक बुलाकर उद्देश्य, इच्छुक सदस्यों की सूची और संस्था का नाम तय किया जाता है।

सहकारिता विभाग अधिकारी

प्रमाणपत्र मिलने का दिन हर गाँव के लिए यादगार होता है, पर अनुभवी सदस्य समय रहते यह भी जोड़ देते हैं कि यह यात्रा की शुरुआत भर है – संस्था प्रमाणपत्र से नहीं, बल्कि ईमानदारी, नियमित बैठकों और सदस्यों के परस्पर विश्वास से आगे बढ़ती है।

पंजीयन के बाद की असली परीक्षा

दो पड़ोसी गाँवों की समितियों का अनुभव इस बात की सबसे बड़ी सीख है। एक समिति में बैठकें नियम से होती रहीं, सदस्य सक्रिय बने रहे, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती गई। दूसरी में बैठकें कम होती गईं, फैसले चंद लोगों तक सिमट गए और आम सदस्य धीरे-धीरे उदासीन होते चले गए। कुछ वर्षों बाद पहली समिति पूरे क्षेत्र के लिए मिसाल बन गई, जबकि दूसरी संघर्ष करती रह गई।

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जब दोनों संस्थाओं का निरीक्षण किया, तो अंतर साफ था – पहली में अभिलेख व्यवस्थित थे, सूचना पट अद्यतन था, सदस्यों में आत्मविश्वास झलकता था; दूसरी में रिकॉर्ड अधूरे थे। उनका निष्कर्ष आज भी सहकारिता क्षेत्र के लिए एक सूत्र वाक्य जैसा है –

जानने योग्य बातें – तैयारी के दौरान इन पर ध्यान दें

- समिति का स्पष्ट उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पहले से तय कर लें।
- इच्छुक सदस्यों की सहमति लिखित रूप में लें।
- संस्था के लिए ऐसा नाम चुनें जो पहले से पंजीकृत किसी समिति से मिलता-जुलता न हो।
- प्रस्तावित उपनियम (बायलॉज) संबंधित अधिनियम एवं नियमों के अनुरूप तैयार करें।
- शुरुआती अंशपूँजी और सदस्यता शुल्क को लेकर स्पष्टता रखें।

आवेदन से प्रमाणपत्र तक की प्रक्रिया

तैयारी पूरी होने के बाद अगला चरण है सक्षम प्राधिकारी – पंजीयक कार्यालय – के समक्ष औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना। इसके साथ प्रस्तावित उपनियम, सदस्यों की सूची, बैठक की कार्यवाही और अन्य निर्धारित दस्तावेज़ संलग्न किए जाते हैं। कार्यालय स्तर पर दस्तावेज़ों की जाँच होती है, आवश्यकता पड़ने पर छोटी-मोटी कमियाँ सुधरवाई जाती हैं और औपचारिक परीक्षण के बाद पंजीयन की स्वीकृति दी जाती है।

यह प्रक्रिया जितनी कानूनी है, उतनी ही भावनात्मक भी। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी की बात इसे बखूबी बयान करती है –

आप लोग किसी योजना का लाभ लेने नहीं, बल्कि अपने गाँव का भविष्य बनाने आए हैं। पहले यह तय कीजिए कि आप सब मिलकर करना क्या चाहते हैं, बाकी प्रक्रिया हम सँभाल लेंगे।

किसी संस्था का भविष्य उसके प्रमाणपत्र से नहीं, उसकी कार्यसंस्कृति से तय होता है।
— जिला सहकारिता अधिकारी

पारदर्शिता और भागीदारी से मिली मज़बूती

सफल समितियों में एक समान पैटर्न दिखता है – हर बैठक में सदस्यों से सुझाव माँगे जाते हैं, रजिस्टर में हर निर्णय और सभा का ब्योरा दर्ज होता है, और अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर बैठकों की सूचना मोबाइल के ज़रिए भेजी जाती है। महिला सदस्यों की सामूहिक पैकिंग और विपणन पहल से न केवल आमदनी बढ़ी है, बल्कि स्वरोजगार के नए अवसर भी बने हैं। खाद-बीज की सामूहिक खरीद से लागत घटी है और संगठित बिक्री से उपज का बेहतर दाम मिलने लगा है।

आपदा जैसी परिस्थितियों में भी यह संगठनात्मक ताकत काम आती है – भारी बारिश जैसी घटनाओं में समितियों ने प्रभावित सदस्यों की सूची बनाकर राहत पहुँचाने में समन्वय किया है, जिससे यह भरोसा और गहरा हुआ कि सहकारी समिति केवल आर्थिक इकाई नहीं, संकट में साथ खड़ा रहने वाला परिवार भी है।

निष्कर्ष – हर क्षेत्र के लिए खुला रास्ता

सहकारी समिति का पंजीयन किसी एक वर्ग या पेशे तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अनेक गाँवों में लोगों ने संगठित होकर सामूहिक खरीद, सामूहिक बिक्री और साझा निर्णयों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति बदली है। यह प्रक्रिया कानूनी पहचान देने के साथ-साथ लोगों को साझा उद्देश्य, साझा मंच और साझा भविष्य भी प्रदान करती है।

जहाँ समान आवश्यकता और सोच वाले लोग साथ आते हैं, वहाँ सहकारी समिति का पंजीयन विकास की दिशा में सबसे प्रभावी पहला कदम बन सकता है – बशर्ते पंजीयन के बाद की ज़िम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया जाए, जितनी गंभीरता से पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

संकलन : श्री पुरूषोत्तम लाल सोनी, व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर

राज्य संघ के प्राधिकृत अधिकारी से संभागीय कार्यालय जगदलपुर के कर्मचारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा से संघ के संभागीय कार्यालय, जगदलपुर के कर्मचारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर कर्मचारियों ने प्राधिकृत अधिकारी का स्वागत करते हुए संघ की विभिन्न गतिविधियों एवं संभागीय कार्यालय द्वारा संचालित सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की।

भेंट के दौरान कार्यालयीन कार्यों, सहकारी संस्थाओं तक सहकारिता की भावना को पहुंचाने तथा ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

इन्होंने की भेंट

इस अवसर पर संभागीय कार्यालय जगदलपुर के जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक विवेक पांडे, मितेश पानीग्राही, सहायक ग्रेड-3 किशोरी लाल ठाकुर एवं जिला सहकारी संघ जगदलपुर के प्रबंधक उपस्थित रहे।

शर्मा ने टीम भावना के साथ काम करने के लिए किया प्रेरित

प्राधिकृत अधिकारी श्री शर्मा ने कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए सहकारी क्षेत्र के विकास एवं संघ की गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि, सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और सदस्य जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। संभागीय कार्यालय द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियों को निरंतर गति देने पर भी जोर दिया गया।

सफल कुक्कुट उत्पादन एवं किसान सशक्तिकरण हेतु उल्लेखनीय प्रयास

बीजापुर। कड़कनाथ छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट देशी कुक्कुट नस्लों में से एक है। यह अपने विशिष्ट काले रंग, स्थानीय एवं कठोर परिस्थितियों में अनुकूलन क्षमता तथा गुणवत्तापूर्ण मांस के लिए प्रसिद्ध है। कड़कनाथ की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए इसे किसानों के लिए अतिरिक्त एवं टिकाऊ आय के संभावित स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

कृषि विज्ञान केंद्र, बीजापुर (पानारापारा) का उद्देश्य ÷हर किसान के घर कड़कनाथ पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से विभिन्न किसानों को कड़कनाथ के चूजे उपलब्ध कराए गए तथा उन्हें उचित ब्रूडिंग, फीडिंग, हाउसिंग, स्वास्थ्य प्रबंधन एवं वैज्ञानिक पालन तकनीकों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

कड़कनाथ मुर्गी के वैज्ञानिक पालन एवं बेहतर उत्पादन तकनीकों के प्रदर्शन एवं प्रसार हेतु दो Front Line Demonstration (FLDs) तथा दो On&Farm Trials (OFTs) भी स्थापित किए गए हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को कड़कनाथ पालन की वैज्ञानिक तकनीकों, बेहतर प्रबंधन practices एवं इसकी उत्पादन क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराया जा रहा है। इन सतत एवं समन्वित प्रयासों के माध्यम से वैज्ञानिक कुक्कुट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण चूजा उत्पादन, बेहतर उत्पादकता तथा किसान स्तर पर तकनीक के प्रसार को बढ़ावा मिला है। भविष्य में इन प्रयासों को और अधिक किसानों तक पहुँचाते हुए कड़कनाथ उत्पादन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने तथा इसे एक sustainable, profitable, oa farmer & centric livelihood model के रूप में विकसित करने का प्रयास जारी रहेगा।

वैज्ञानिक कुक्कुट प्रबंधन से बेहतर उत्पादन, कड़कनाथ के प्रसार से किसान सशक्तिकरण तथा 'हर किसान के घर कड़कनाथ' के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर एक सार्थक पहल।

धमतरी जिले के पहले देवभोग मिल्क पार्लर का कुरूद में शुभारंभ

कुरूद। धमतरी जिले में सहकारिता एवं दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कुरूद में जिले के प्रथम देवभोग मिल्क पार्लर का शुभारंभ माननीय विधायक श्री अजय चंद्राकर जी के करकमलों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर नगर पालिका परिषद, कुरूद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति भानु चंद्राकर जी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) के उप प्रबंध संचालक, डॉ. सैकत सामंत, विपणन प्रमुख श्री अजय सिंह मीना, विपणन विभाग के अधिकारीगण तथा अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

विधायक चंद्राकर ने की सराहना: कार्यक्रम के दौरान विधायक श्री अजय चंद्राकर ने देवभोग मिल्क पार्लर की स्थापना की सराहना करते हुए कहा कि, इस प्रकार की पहल से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध एवं दुग्ध उत्पाद सहजता से उपलब्ध होंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) को धमतरी जिले के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी देवभोग

मिल्क पार्लर स्थापित करने का सुझाव दिया, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके तथा स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो।

एक ही स्थान पर मिलेंगे देवभोग के विभिन्न उत्पाद: धमतरी जिले के प्रथम देवभोग मिल्क पार्लर के प्रारंभ होने से कुरूद एवं आसपास के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दूध, दही, पनीर, घी, लस्सी, श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क, मिष्ठान सहित देवभोग के विभिन्न दुग्ध उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। यह मिल्क पार्लर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बेहतर बाजार से जोडने़ की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इससे दुग्ध सहकारी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी तथा दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सहकारिता से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ

देवभोग मिल्क पार्लर की स्थापना सहकारिता के माध्यम से उत्पादक से उपभोक्ता तक गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद पहुंचाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इससे स्थानीय स्तर पर दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही सहकारी दुग्ध व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का करें समयबद्ध क्रियान्वयन

प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले शासन की योजनाओं का लाभ : सीएम साय

रायपुर। शासन की योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर आमजन को अधिकतम लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना है। इसी दृष्टि से शासन की प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की नियमित निगरानी के लिए विकसित पारस पोर्टल सुशासन का एक प्रभावी माध्यम बनेगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विगत दिनों मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस पोर्टल की पहली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु, एग्रीस्टैक, विकसित भारत जी-रामजी, डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल टॉवर परियोजना तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित करे।

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री की नाराजगी: बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने राजस्व विभाग में सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद भी कई मामलों में समय पर सीमांकन नहीं हो रहा है। यह स्थिति आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालती है तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह जमीनी स्तर पर लापरवाही तथा जिला स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव का परिणाम है। सभी कलेक्टर नियमित समीक्षा कर ऐसे मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करें।

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह केवल धान खरीदी की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि

सीएम हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी जनसमस्या समाधान का माध्यम

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 का उद्देश्य नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से बचाना है। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इसलिए प्राप्त शिकायतों और फीडबैक का गंभीर विश्लेषण कर व्यवस्थागत सुधार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतों की विशेष समीक्षा करते हुए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है, वहां विशेष अभियान चलाकर शिकायतों का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में अब तक एक लाख 10 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। प्राप्त फीडबैक में 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने सकारात्मक संतुष्टि व्यक्त की है।

सेवा सेतु के माध्यम से सभी सेवाएं हों ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु पोर्टल की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में 27 विभागों की 721 अधिसूचित सेवाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन सेवाओं को अभी तक ऑनलाइन नहीं लाया गया है, उन्हें भी शीघ्र सेवा सेतु से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर तथा अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवा सेतु का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक नागरिक घर के निकट ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

विकसित भारत जी-रामजी योजना में ग्राम पंचायतों को मिले प्राथमिकता

बैठक में विकसित भारत जी-रामजी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए। जिन पंचायतों में अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहां तत्काल प्रस्ताव स्वीकृत कर विकास कार्य प्रारंभ किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत अधोसंरचना को तेजी से सुदृढ़ किया जा सके।

किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की आधारभूत व्यवस्था है।

उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिलेवार विशेष अभियान संचालित कर प्रत्येक पात्र किसान का समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आई थीं, लेकिन इस वर्ष किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण कोई पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित होता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

मोबाइल कनेक्टिविटी और स्कूल शिक्षा की भी हुई समीक्षा: बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल देते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।

स्कूलों में पोषण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर: मुख्यमंत्री श्री साय ने स्कूल परिसरों में किचन गार्डन विकसित करने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को ताजा एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्कूल परिसरों में सहजन, कटहल सहित अन्य उपयोगी पौधों के रोपण पर भी विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को पोषणयुक्त भोजन के महत्व से अवगत कराया जाए, ताकि वे स्वप्रेरणा से इस अभियान से जुड़ें और विद्यालयों में विकसित हो रही इस सकारात्मक पहल को जनआंदोलन का स्वरूप मिल सके।

प्रत्येक माह होगी पारस पोर्टल के माध्यम से समीक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल शासन की योजनाओं की प्रभावी निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा की कि अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से राज्य स्तर पर सभी प्रमुख योजनाओं एवं जनसेवाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, समस्याओं का समय पर समाधान होगा और जनता तक शासकीय सेवाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा।

दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिए दिया गया किसान जागरूकता प्रशिक्षण

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा पशुपालकों को वैज्ञानिक एवं आधुनिक पशुपालन पद्धतियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बी.एम.सी. संण्डी, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में किसान जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित (देवभोग) के उप प्रबंध संचालक डॉ. सैकत सामंत द्वारा उपस्थित किसानों एवं पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन तथा वैज्ञानिक पशुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

वैज्ञानिक पशुपालन से बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन

प्रशिक्षण के दौरान पशुपालकों को पशुओं के संतुलित पोषण एवं बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से निम्न विषयों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया–

साइलेज (Silage) बनाने की विधि एवं उपयोग

हरे चारे का उत्पादन, संरक्षण एवं पशुओं को

संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराने की विधि

थनैला रोग (Mastitis) की पहचान, रोकथाम एवं उपचार संबंधी सावधानियां

पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियां एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन दुधारू पशुओं के पोषण एवं देखभाल की वैज्ञानिक पद्धतियां दुग्ध उत्पादन एवं गुणवत्ता में सुधार के उपाय

महिला पशुपालकों की उल्लेखनीय भागीदारी

कार्यक्रम में महिला पशुपालकों की उत्साहपूर्ण एवं उल्लेखनीय भागीदारी रही। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई तथा दुग्ध व्यवसाय को आय का स्थायी एवं लाभकारी माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दुग्ध उत्पादकों को वैज्ञानिक पशुपालन से जोडने़, दुग्ध उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा सहकारी दुग्ध व्यवस्था के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

आहार और स्वास्थ्य का असर

प्रशिक्षण के दौरान पशुपालकों को बताया गया कि, पशुओं के उचित पोषण, स्वच्छता, समय पर स्वास्थ्य जांच तथा संतुलित आहार का दुग्ध उत्पादन एवं दूध की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाकर पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाथ में तिरंगा थामकर किया भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

- मुख्यमंत्री ने कहा – 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है तिरंगा
- हजारों कदमों के साथ गूंजा 'राष्ट्र सर्वोपरि' का संकल्प
- तिरंगे के रंग में रंगा रायपुर, राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुआ जनसैलाब
- छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों की शौर्यगाथा का किया स्मरण, शहीद वीर नारायण सिंह और गुण्डाधुर को किया नमन

रायपुर। हाथों में लहराता तिरंगा, भारत माता के जयघोष, देशभक्ति के गीत और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हजारों नागरिकों का उत्साह - राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थामा गया लगभग एक किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता के जयघोष ने पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्रप्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। इस दौरान नागरिकों में मुख्यमंत्री के साथ चलने और राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। यह केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे में देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तिरंगा लहराता है तो प्रत्येक भारतीय के मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जागृत होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का साक्षी है। तिरंगा हमें अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान आज एक व्यापक जनअभियान का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान ने तिरंगे को घर-घर तक पहुंचाने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में पूरे सम्मान और गौरव के साथ तिरंगा फहराने तथा तिरंगा यात्राओं से जुड़कर राष्ट्रीय एकता के इस उत्सव को और भव्य बनाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में गर्व और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, वह स्वतंत्रता हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान जुड़ा हुआ है। देश के असंख्य वीर सपूतों ने मातृभूमि को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर क्षेत्र और समाज के लोगों ने अपना योगदान दिया। किसी ने अपना जीवन समर्पित किया, किसी ने अपना घर-परिवार छोड़ा और अनेक वीरों ने मातृभूमि के लिए हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन बलिदानों के कारण ही आज हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के गौरव का अनुभव कर पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की नई पीढ़ी स्वतंत्र भारत में जन्मी और आगे बढ़ रही है। इसलिए उसे यह जानना आवश्यक है कि आजादी कितनी अनमोल है और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानियों की गौरवगाथाओं से परिचित होकर ही नई पीढ़ी स्वतंत्रता के वास्तविक मूल्य को समझ सकेगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें उन सभी ज्ञात-अज्ञात सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता की इस गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इससे युवाओं के भीतर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समर्पण, सेवा और 'राष्ट्र प्रथम' का भाव और अधिक मजबूत होगा।

'छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में लिखी शौर्यगाथा'

मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भी वीरों, जननायकों और बलिदानियों की धरती रही है। देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अदम्य साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों के हित में आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका जीवन हमें बताता है कि राष्ट्रप्रेम के साथ जनसेवा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी सच्ची देशभक्ति का स्वरूप है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर के महान जननायक गुण्डाधुर की शौर्यगाथा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर संघर्ष का बिगुल फूंका। बस्तर की धरती ने सदैव अपने स्वाभिमान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। गुण्डाधुर का साहस और नेतृत्व आज भी छत्तीसगढ़वासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधुर सहित छत्तीसगढ़ के अनेक ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष हमारे गौरवशाली इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इन महानायकों की शौर्यगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके आदर्शों से युवाओं को परिचित कराना हमारा दायित्व है।

'बदलते बस्तर में शांति और विकास के साथ लहराएगा तिरंगा'

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर आज हिंसा और भय के लंबे दौर को पीछे छोड़कर शांति, विश्वास और विकास की नई दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और क्षेत्रवासियों के सहयोग से नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंची है। उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी नक्सली हिंसा के कारण भय का वातावरण था, वहां अब विकास की नई रोशनी पहुंच रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों का शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। बस्तर के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते बस्तर की पहचान अब हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, विश्वास और नई संभावनाओं से बन रही है। इस वर्ष बस्तर में भी स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा तथा तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। बस्तर के गांवों और दूरस्थ अंचलों में भी तिरंगा पूरे गौरव के साथ लहराएगा।

महानदी विवाद नहीं, छत्तीसगढ़-ओडिशा की साझा समृद्धि का आधार बने : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक

रायपुर। महानदी जल बंटवारे से जुड़े विषयों के सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान की दिशा में विगत दिनों नई दिल्ली स्थित श्रमशक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण पहल हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों की साझा जीवनरेखा है। इसका जल किसानों की आजीविका, पेयजल व्यवस्था, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बैठक को किसी विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संवाद और सहयोग का जो वातावरण बना है, वह भविष्य में स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान का मजबूत आधार बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ओडिशा की सिंचाई, पेयजल तथा हीराकुंड परियोजना से जुड़ी आवश्यकताओं का पूरा सम्मान करती है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी अंचलों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा राज्य की भविष्य की विकास आवश्यकताओं को भी समान संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के हित एक-दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं और समाधान भी ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी पक्ष के हित प्रभावित न हों।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के विशेषज्ञ उपलब्ध जल की मात्रा तथा उससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर चुके हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन तकनीकी निष्कर्षों के आधार पर भविष्य उन्मुख एवं व्यवहारिक व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले सालों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की जाए, जिससे किसी भी राज्य को कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्थायी संस्थागत तंत्र विकसित किया जाए, जो समय-समय पर जल उपलब्धता, उपयोग और आवश्यकताओं की समीक्षा करता रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रशासनिक एवं तकनीकी स्तर पर अधिकतम विषयों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए तथा केवल नीतिगत महत्व के विषयों को ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर विचार के लिए लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल तथा केंद्रीय जल आयोग से अनुरोध किया कि वे निष्पक्ष तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने, समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सकारात्मक पहल दोनों राज्यों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी तथा समाधान की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सहकारी संघवाद और राज्यों के बीच समन्वय की भावना ने वर्षों से लंबित जटिल विषयों के समाधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में दोनों राज्य मिलकर ऐसा समाधान विकसित करेंगे, जिससे किसानों, नागरिकों, उद्योगों, पर्यावरण तथा भावी पीढ़ियों का जल भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बने।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शहरी सहकारी बैंकों को मिलेगा आधुनिक तकनीक और साइबर सुरक्षा का मजबूत आधार

मुंबई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को आगे बढ़ाते हुए देश के शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मुंबई में आयोजित 'सहकार नव-क्रांति' कार्यक्रम में शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभिन्न आधुनिक सेवाओं का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर NCFDC के नवनिर्मित कार्यालय परिसर का उद्घाटन भी किया गया।

कार्यक्रम में शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) तथा राष्ट्रव्यापी सेवा बंडल के अंतर्गत कोर बैंकिंग एवं अन्य आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही, NCFDC और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFS) के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंकों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में लगभग 1,400 शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि है। ये बैंक छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, कुटीर उद्योगों, रूस्रूश्व, स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा मध्यम वर्ग के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी सहकारी बैंकों के लिए बनाए गए अम्ब्रेला संगठन का उद्देश्य इन बैंकों को तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना, नियामकीय अनुपालन को सरल बनाना तथा उन्हें आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से बैंकों को आवश्यक सॉफ्टवेयर, तकनीकी समाधान एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

'Bank in a B& से छोटी शाखाओं को भी आधुनिक बैंकिंग सुविधा

कार्यक्रम में Bank in a B&' सेवा का शुभारंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड सेवाएं, नियामकीय अनुपालन तथा आधुनिक बैंकिंग से जुड़ी सुविधाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस पहल से छोटी शाखाओं एवं सीमित संसाधनों वाले शहरी सहकारी बैंकों को भी अपेक्षाकृत कम लागत पर आधुनिक एवं विश्वस्तरीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक पर विशेष जोर

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए NCFDC और NF के बीच हुए समझौते को महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक, अनुसंधान एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। शहरी सहकारी बैंकों के लिए शुरू किया गया सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे साइबर निगरानी, त्वरित मार्गदर्शन एवं सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे बैंक, उनके ग्राहक एवं जमाकर्ता बढ़ते डिजिटल जोखिमों से अधिक सुरक्षित हो सकेंगे।

'सहकार से समृद्धि' के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित एवं समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है।

306 करोड़ रुपये की पूंजी से साकार हुआ अम्ब्रेला संगठन

श्री अमित शाह ने बताया कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन की स्थापना एक बड़ी चुनौती थी। सहकारी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों के सहयोग से लगभग 306 करोड़ रुपये की पूंजी एकत्रित की गई और संगठन की विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि अम्ब्रेला संगठन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि शहरी सहकारी बैंकों को व्यवस्थित करना, उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना तथा आवश्यकता के समय उन्हें सहयोग प्रदान करना है।

सहकारिता से छोटे पूंजी निवेश को बनाया जा सकता है बड़ी आर्थिक शक्ति

श्री अमित शाह ने सहकारिता की मूल शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि छोटे-छोटे लोगों की छोटी-छोटी पूंजी को सहकारिता के माध्यम से एकत्रित कर बड़ी पूंजी का निर्माण किया जा सकता है और उसके आधार पर बड़े व्यावसायिक संस्थान खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने अमूल, IFFCO, RIB HCO एवं लिज्जत पापड़ जैसी सफल सहकारी संस्थाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि इनकी सफलता व्यापक जनभागीदारी और लाखों सदस्यों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

पेज 01 का शेष ....
सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए .....

बायलॉज़ में संशोधन से सहकारी संस्थाओं को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की तैयारी

बायलॉज में सकारात्मक और विस्तृत संशोधनों पर सहमति बनी है ताकि सहकारी संस्थाओं के नियम-नियमावली में प्रासंगिक सुधार लाया जा सके। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिक उत्तरदायी, समावेशी और लचीली संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है। संशोधनों में सदस्यता की सहजता, बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं के संचालन के स्पष्ट मानदंड, पदाधिकारियों की उत्तरदायित्व सीमा, आचार संहिता और विवाद समाधान प्रक्रिया जैसे विषयों को शामिल किया गया है। इससे यह आशा की जा रही है कि छोटे और मध्यम स्तर के सहकारी समूह अधिक कुशल होकर स्थानीय स्तर पर विकास-अभियान चला सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि बायलॉज संशोधनों पर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसमें सदस्यों की राय भी शामिल की जाएगी और अंतिम मसौदा सार्वजनिक सुझावों के बाद अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य सहकारी संघ की सदस्यता सभी जिला संघों के लिए अनिवार्य करने का निर्णय

राज्य सहकारी संघों तथा जिला सहकारी संघों के संबंध में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि सभी जिला संघों को राज्य सहकारी संघों की सदस्यता अनिवार्य रखी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य समन्वय बढ़ाना, संसाधनों का केंद्रीकृत उपयोग आसान करना और नीति-निर्माण में एकरूप दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। सदस्यता अनिवार्यता से जिला संघों को राज्य स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षण, वित्तपोषण और तकनीकी सहायता का लाभ मिलेगा और साथ ही राज्य नीतियों का निष्पादन जिलेवार सुसंगत रूप से हो सकेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से स्थानीय स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी; बल्कि सदस्यता के माध्यम से साझा संसाधनों और बाजार पहुंच का लाभ जिले को मिलेगा।

स्थानीय महिला समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने की नई पहल

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य संघ एवं जिला संघों में कार्यालयों में स्थानीय स्वयं सहायता समूह (सात्र) की बहनों द्वारा तैयार स्थानीय नाश्ते को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति से महिला स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और कार्यालयों में स्थानीय उत्पादों का प्रयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही, काजू, बादाम, पिस्ता जैसे महंगे और आयात-आधारित नाश्तों पर पाबंदी कराकर स्थानीय, सस्ते और मौसमी नाश्तों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने इसके पीछे का तर्क यह रखा कि सरकारी व संस्थागत बैठकों में स्थानीय उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने से स्थानीय किसानों व स्वरोजगारियों को स्थिर मांग मिलेगी और खर्च भी नियंत्रित रहेंगे। इस नीति का सामाजिक आयाम यह है कि महिलाओं की स्वरोजगार गतिविधियाँ सशक्त होंगी तथा शुद्धता, स्वास्थ्य-संबंधी मानक और भोजन सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ मानक तय किए जाएंगे।

शिकायत निवारण पोर्टल और युवा उद्यमियों के लिए इनक्यूबेशन योजना प्रस्तावित

इन विषयों के अतिरिक्त, बोर्ड ने दो अतिरिक्त बिंदु जोड़े – (1) सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने हेतु विशेष शिकायत निवारण पोर्टल का निर्माण, और (2) युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप-इनक्यूबेशन स्कीम। शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से सदस्य, ग्राहक या आम नागरिक किसी भी अनियमितता, गड़बड़ी या वित्तीय शोषण की शिकायत दर्ज कर सकेंगे; शिकायतों की समयबद्ध जांच और समाधान के लिए एक कड़ा समयबद्ध ढांचा रखा गया है। दूसरी तरफ़ स्टार्टअप-इनक्यूबेशन स्कीम का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के भीतर नवाचार को उत्प्रेरित करना है – युवा सदस्य छोटे व्यवसाय, कृषि-प्रौद्योगिकी समाधान और ग्रामीण लघु-उद्योग की शुरुआत कर सकेंगे और जिला स्तर पर चयनित सफल पहलों को राज्य स्तर की सहायता और बाज़ार की पहुँच दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्यमिता को सहकारिता से जोड़ने पर जोर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 15 अगस्त के भाषण में सहकारिता से जुड़े जो पहलू आए, उन्हें भी बैठक में संदर्भित किया गया और उन बिंदुओं के अनुरूप राज्य स्तर पर ठोस कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सहकारिता को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम साधन बताया और कहा कि सहकारी मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती देता है, महिलाओं और छोटे किसानों को सशक्त बनाता है तथा स्थानीय उत्पादन और स्थानीय बाज़ार को प्रोत्साहित करता है। बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाकर, बाज़ार-केंद्रित और तकनीकी रूप से शक्तिशाली बनाना प्राथमिकता होगी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री के भाषण के सार को ध्यान में रखते हुए राज्य ने स्थानीय उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण और कृषि-आधारित सहकारी मूल्य-श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कदमों का निर्धारण किया है।

सहकारी संस्थाओं के उत्पादों के लिए समन्वित विपणन नीति की तैयारी

राज्य बोर्ड ने यह भी प्रस्ताव रखा कि सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाक़ों में संचालित करने हेतु विशेष टैक्स-प्रोत्साहन व अनुदान योजना के साथ-साथ बाज़ार पहुँच की गारंटी देने के लिए राज्य मंडियों और ई-मार्केटिंग पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा। यह योजना सहकारी उत्पादक समूहों को स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों बाजारों तक पहुँचाने में मदद करेगी। बोर्ड ने राज्यों के सफल मॉडलों का अध्ययन करने और उन मॉडलों को स्थानीय संदर्भ में अपनाने हेतु एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से आधुनिक सहकारी नेतृत्व विकसित करने की पहल

बैठक के दौरान प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्तावित कार्यक्रमों में सहकारी प्रबंधन पर डिप्लोमा-स्तर के प्रशिक्षण, लेखा-जब्ती और कराधान से संबंधित कार्यशालाएँ, और डिजिटल बैंकिंग तथा मोबाइल-पेमेन्ट सिस्टम पर प्रशिक्षण शामिल हैं। बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया कि जिला स्कूलों और कॉलेजों में सहकारीता के सिद्धांतों पर पाठ्यक्रम और कार्यशालाएँ शामिल की जाएँ ताकि युवा पीढ़ी में सहकारी भावना को जड़ें मिले और वे भविष्य में सहकारी संस्थाओं को और आधुनिक बनाएं।

ऑडिट एवं निगरानी के लिए स्वतंत्र उप-आयोग गठित करने का प्रस्ताव

ऑडिट व निगरानी संरचना को और मजबूत करने के लिये राज्य में एक स्वतंत्र निगरानी उप-आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। यह उप-आयोग समय-समय पर जिला संघों और राज्य संघों के वित्तीय व्यवहार, ॠण नीतियों, सदस्यता रिकॉर्ड और आचार-संहिता का ऑडिट करेगा। उप-आयोग की रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार और सहकारी बोर्ड दोनों को प्रसारित की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई हो सके।

साथ ही, सहकारी संस्थाओं के लिए एक समन्वित विपणन नीति तैयार करने पर सहमति बनी जिससे सहकारी उत्पादों का ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और बाज़ार-संगठित वितरण पर काम किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत सहकारी उत्पादों के लिए अलग ब्रांड नाम, मानक पैकेजिंग, और गुणवत्तापरख परीक्षण की व्यवस्था लाई जाएगी ताकि उपभोक्ता स्तर पर विश्वास बन सके। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पर सहकारी उत्पादों के लिए समर्पित केटलॉग तैयार करने का विचार भी प्रस्तावित किया गया है।

बोर्ड ने यह भी जोर दिया कि सहकारी संस्थाओं की जवाबदेही में सुधार लाने हेतु पदाधिकारियों के चुनाव के बाद उनकी नियमित रिपोर्टिंग और प्रदर्शन मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए। इसके लिये प्रदर्शन सूचकांक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें वित्तीय स्वास्थ्य, सदस्य संतुष्टि, ॠण वसूली दक्षता और सामाजिक प्रभाव जैसे मानदण्ड शामिल होंगे। ये सूचकांक संवारने का मकसद यह है कि मद संचित न होकर कार्य-प्रणाली में सुधार आए और पदाधिकारी वास्तविक परिणामों के आधार पर आकलित हों।

कृषि आधारित सहकारी उद्यमों और सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में फ़सल-आधारित सहकारी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये सूक्ष्म-प्रक्रिया इकाइयों स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। इन इकाइयों में कृषि-उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण होगा जिससे किसानों की उपज का मूल्य बढ़ेगा और उत्पादों का शेर-मार्केट में बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा। यह कदम स्थानीय मूल्य-श्रृंखला को मज़बूत करेगा तथा सहकारी संस्थाओं को स्थानीय उद्योगों के रूप में स्थापित करेगा।

बिलासपुर जिला संघ के परिसीमन से बाहर किए जाने के निर्णय के प्रभावों पर विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि यह बदलाव लंबी अवधि में प्रशासनिक दक्षता बढ़ा सकता है परन्तु संक्रमण काल में सदस्यता संबंधी दिक्कतें और कार्यालयीय समन्वय की चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। अतः बोर्ड ने संक्रमण को सहज बनाने के लिये एक तीन-स्तरीय संक्रमण योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दियाः तत्कालीन संवहनीय मामलों की सूची, सम्पत्ति व दायित्वों का अदल-बदल, तथा नई सीमाओं के अनुरूप प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण। महासमुंद में जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर यह स्पष्ट किया गया कि नियुक्तियाँ पारदर्शी शिकायत मार्ग और योग्यता मानदंडों के तहत की जाएँगी ताकि स्थानीय समुदायों का विश्वास बना रहे।

जन-सहभागिता से बायलॉज संशोधन और सहकारी जागरूकता अभियान को गति

नए बायलॉज संशोधनों के साथ एक व्यापक जन-सहभागिता अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। इस अभियान के तहत ग्राम स्तर पर बैठकें, रेडियो और स्थानीय टीवी चैनलों पर कार्यक्रम, और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैनल आयोजित किए जाएँगे। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि सहकारिता केवल ॠण देने वाली संस्था नहीं है बल्कि स्थानीय विकास, सेवाओं और बाज़ार की पहुँच सुनिश्चित करने वाली एक व्यवस्था है।

बोर्ड ने यह भी कहा कि सहकारी OTT पर तैयार होने वाली सामग्री का कंटेंट स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों, समेकित विपणन विशेषज्ञों और अनुभवी सहकारी प्रबंधकों की सहायता से विकसित किया जाएगा। OTT पर लाइव सत्रों के साथ-साथ कैप्सूल-आधारित वीडियो, पॉडकास्ट और प्रमाणपत्र-युक्त कोर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्लेटफ़ॉर्म उन क्षेत्रों में भी काम आएगा जहाँ भौगोलिक दूरी के कारण प्रशिक्षण पहुँचाना कठिन है। OTT की सदस्यता का लाभ लेने के लिये सहकारी सदस्यों के लिये सब्सिडी मॉडल पर विचार चल रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य भी प्रशिक्षण से जुड़ सकें।

स्थानीय नाश्ते नीति पर उठाए गए कदम का स्वागत सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने किया है। उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वरोजग़ार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय खाद्य श्रृंखला को मजबूती मिलेगी। हालांकि कुछ उद्योगों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई कि महंगे सूखे मेवे बंद करने से खाद्य विविधता पर असर पड़ सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों के लिए बाजार सीमित होगा। बोर्ड ने इस आपत्ति का निवारण करते हुए कहा कि महंगे विकल्पों को पूरी तरह प्रतिबंधित न करके, वे केवल औपचारिक बैठकों और सरकारी कार्यक्रमों में प्राथमिकता नहीं दिए जाएंगे; निजी आयोजन अपनी नीति स्वतन्त्रता के साथ कर सकेंगे। साथ ही, स्थानीय नाश्तों की गुणवत्ता और पोषण मानकों को बनाए रखने के लिये तहसील स्तर पर निरीक्षण और ट्रेनिंग का प्रावधान होगा।

समाप्ति में, राज्य बोर्ड ने घोषणा की कि इन निर्णयों का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से अगले छह महीनों में किया जाएगा और समय-समय पर प्रगति की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाएगी ताकि नागरिक और सदस्यों को पता रहे कि किन-किन बिंदुओं पर कितना काम हुआ है। बोर्ड ने राज्यों और केंद्र के सहयोग से संसाधन जुटाने और विशेषज्ञ सहायता लेने का संकल्प भी जताया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन पहलों को संजीदगी से लागू किया जाए तो छत्तीसगढ़ का सहकारी ढांचा न सिर्फ़ अधिक जवाबदेह और टिकाऊ बनेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमशीलता को भी ठोस समर्थन मिलेगा। वहीं, चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं – परिसीमन से जुड़ी कानूनी जटिलताएँ, चुनाव प्रक्रिया में असमानताएँ, बायलॉज संशोधनों पर व्यापक सहमति जुटाने की कठिनाई और OTT तथा डिजिटल पहलों में ग्रामीण कनेक्टिविटी की सीमाएँ प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। इन जोखिमों को प्रबंधित करने के लिये बोर्ड ने सतत निगरानी, पारदर्शी रिपोर्टिंग और व्यापक जन-सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया है। यह घोषणा और निर्णय राज्य के सहकारी इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के समान हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सरलीकरण के साथ साथ स्थानीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में भी निर्णायक साबित होंगे।

सहकारिता और विकसित भारत

डॉ. अनन्त दीक्षित

सहकारिता को समझने के लिये हमें इसके सामान्य अर्थ (सह + कार्य) से आगे बढ़कर इसके विशिष्ट अर्थ को समझना होगा। सहकारिता एक आर्थिक गतिविधि है। यह समान हित रखने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन है। इसमें सदस्य मिलकर पूंजी लगाते हैं और परस्पर सहयोग से व्यवसाय का संचालन कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संगठन का नियमानुसार पंजीयन करवाना भी आवश्यक होता है।

सहकारिता के सम्बन्ध में यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिये कि सहकारी संस्थायें दवि उदेश्य वाली होती हैं। व्यावसायिक इकाई के रूप में इन्हें बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों से प्रतियोगिता करनी होती है, दूसरी ओर इन्हें अपने सदस्यों के हितों का भी ध्यान रखना होता है, जो सामान्यतः इसके छोटे अंशधारी होते हैं तथा अपनी आजीविका के संकट से भी जूझ रहे होते हैं। इस प्रकार एक सहकारी संस्था ÷उपयोगकर्ता स्थायित्व' वाली संस्था होती है, न कि ÷निवेशक स्थायित्व'' वाली। दूसरे शब्दों में सहकारिता एक व्यावसायिक गतिविधि होने के साथ-साथ एक सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक अनुष्ठान भी है। यह हमें पूंजीवाद के शोषण और समाजवाद की गुलामी से बचाते हुए अपने जीवन को सुधारने का अवसर प्रदान करती है।

इस आधुनिक सहकारिता का जन्म इंग्लैण्ड में 1844 में हुआ, जब राबर्ट ओवन के विचारों से प्रभावित होकर रोशडेल के 28 बुनकरों ने अपना एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार बनाया । इनके बनाये ढा सिद्धान्त आज भी सहकारी समितियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सहकारिता के अध्ययन में इन्हें 'रोशडेल 7 के अग्रगामी'? कहा जाता है। साख सहकारिता का मॉडल जर्मनी में शुल्जे एवंरेफेशन ने विकसित किया।

भारत में सहकारिता की औपचारिक शुरूआत 1904 में पहली सहकारी साख समिति के गठन से होता है। 1912 के बाद कृषि साख के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में भी सहकारी समितियों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद योजनाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व 1951-52 में सहकारी समितियों की संख्या 1.86 लाख थी जो कि आज बढक़र 8.55 लाख से अधिक हो गई है। इन समितियों में सदस्यों की कुल संख्या 30 करोड़ के लगभग है। यह संख्या विश्व के अनेक देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है।

भारत जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बाले देश में सहकारिता ग्रामीण आर्थिक विकास की धुरी बन सकती है। सहकारी संस्थायें कृषि विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा सामाजिक समावेशन के ड विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का री उपयोगी माध्यम है। किन्हीं कारणों से 2021 के पहले तक हमारे देश में सहकारिता को पूर्णतः राज्यों के जिम्मे छोड़ दिया गया था। इस कारण देश में एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति या कार्यक्रम का अभाव हमेशा खटकता रहता था। 06 जुलाई 2021 को केन्द्र सरकार में एक पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन होने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में आज एक नई ऊर्जा एवं उत्साह दिखलाई दे रहा है।

मंत्रालय गठन के बाद सहकारिता के विकास के अनेक उपाय एवम् प्रयल किये गये हैं। जिन्हें "सहकार की समृद्धि" का नाम दिया गया है। इन प्रयासों में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में सुधार कर उन्हें बहुउद्देशीय बनाना, उन्हें नई गतिविधियों में जोड़क़र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप नेस्थापित करना, जिला सहकारी बैंकों एवं शहरी सहकारी बैंकों में सुधार, बहुराज्यीय सहकारी समितियों E का गठन, सहकारी चीनी मिलों को सहायता एवं सुधार, सहकारिता में नवाचार को प्रोत्साहन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की उन्नत व्यवस्था, एक पृथक सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सहकारिता को मजबूत करने हेतु नई सहकारिता नीति को अंगीकार करना प्रमुख है।

हर गांव पंचायत को सहकारिता के क्षत्र में लाने के प्रयास के चलते सहकारी समितियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है तथा यह 9 लाख के समीप पहुँच गई है। केबल पैक्स की संख्या ही 1 लाख से अधिक हो गई है। पैक्स आज कृषि साख के 3696 भाग को पूरा कर रहे हैं जबकि ग्रामीख साख का 20% भाग इन पैक्स द्वारा पोषित है। पैक्स आज समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद, उचित मूल्य की दुकानों का 7 संचालन तथा कृषि उपज के भण्डारण का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे है। ग्रामीण स्तर पर भण्डारण का 55.5 प्रतिशत भाग तथा उचित मूल्य की दुकानों का 20.3 प्रतिशत भाग पैक्स द्वारा ही संचालित हो रहा

अन्य क्षेत्र में भी सहकारिता का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। आज उर्वरक उत्पादन का 3096, उर्वरक वितरण का 359 सहकारिता के द्वारा हो रहा है। देश के कुल चीनी उत्पादन में सहकारी चीनी मिलों का योगदान 45% है। सहकारी समितियों ने दुग्ध उत्पादन में क्रांति ला दी है। अमूल जैसी सहकारी संस्थायें 7 अनेक राज्यों में क्रियाशील है जो रोज 1.6 करोड़ किसानों से 30 मिलियन लीटर दूध खरीदती है। समितियों के किसानों को प्रोत्साहन के कारण आज हम 220 मिलियन मीट्रिक लीटर का वार्षिक उत्पादन कर 7 विश्व में पहले स्थान पर है।

छोटे किसान, बुनकर, वनोपज संग्राहकों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति में सुधार कर सहकारिता 7 ने इनके जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है। देश में 27000 से अधिक प्राथमिक मत्स्य समितियाँ अपने 40 लाख सदस्यों की गरीबी को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ग्रामीण परिवहन का 189 भाग 7 सहकारिता द्वारा संचालित है। अब तो भारत टैक्सी योजना के जरिये शहरी परिवहन में भी सहकारिता ने दस्तक दे दी है। यह भी रेखांकित किये जाने योग्य है कि आज कुल समितियों में 1296 समितियाँ महिला नेतृत्व वाली हैं। अर्थात् सहकारिता महिला सशक्तिकरण में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सहकारिता 7 में कुल 20 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है जो कि कुल रोजगार का 139% है। फसल खरीद, अनाज भण्डारण जैसे अवसरों पर उत्पन्न होने वाला अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी रोजगार भी ग्रामीणों के लिये वरदान है।

उक्त विवरण के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि सहकारिता के सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र के समावेशी विकास लाभों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक खेती, आय का समान वितरण, सामाजिक सद्भाव जैसे लक्ष्यों को सहकारिता सीधे सम्बोधित करती है।

इन सारी धारणाओं एवं सरकार के द्वारा सहकारिता के विकास हेतु किये जा हहे प्रयत्लों के बावजूद हमारे देश में सहकारिता की उत्पादकता निराशाजनक ही रही है। सहकारिता की असफलता को बतलाते हुए प्रायः यह कहा जाने लगा है कि भारत में समितियाँ बढ़ी हैं, सहकारिता का बढ़ना अभी शेष है'' या सहकारिता का पौधा विदेशों से लाकर देश में रोपित किया गया है, यह पौधा बड़ा तो हुआ है परन्तु इसमें 7 आशानुरूप फल नहीं लगे।'

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें सहकारी क्षेत्र की कमजोरियों एवं उसके i समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्रातिशीघ्र सहकारी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 7 प्रयास करना होगा।

1 . राज्य सूची का विषय होने के कारण प्रायः सहकारिता के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य में टकराव बना रहता है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस समस्या के निराकरण की आशा है।

2. सहकारी समिति के सदस्यों का व्यवहार प्रायः गैर जिम्मेदार होता है। बे समिति की बैठकों में 7 गम्भीरता से भाग नहीं लेते। इस हेतु पहल एवं प्रेरणा आवश्यक है।

3. अधिकांश सहकारी समितियाँ सरकारी सहायता पर निर्भर होती है। जिसके कारण इनके संचालन में राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ता है।

4. यह राजनैतिक हस्तक्षेप प्रायः अपने समर्थकों को समिति के पदों पर बैठाने एवं अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है।

5. कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण व्यवसाय के संचालन हेतु कुशल एवं पेशेवर कर्मचारियों को आकर्षित करने में संस्थायें असफल रहती है।

6. अधिकांश सहकारी संस्थायें एक सरकारी विभाग की तरह काम कर रही हैं तथा सरकारी क्षेत्र तमाम अकुशलतायें यहां भी व्याप्त हो गई है।

7. यद्यपि सहकारिता के लोकतांत्रिक स्वरूप की बहुत प्रशंसा की जाती है परन्तु समय पर निर्वाचन न करवाने के कारण ये तदर्थवाद पर संचालित हो रही है।

8. सहकारी वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बंक और सहकारिता विभाग का दोहरा नियंत्रण उनकी व्यावसायिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अकुशलता एवं भ्रष्टाचार के कारण सहकारी बैंकों की असफलता के किस्से प्रायः पढ़ने में आते हैं।

9. संस्था के कर्मचारियों एवं संचालकों के लिये समुचित एवं प्रभावी प्रशिक्षण अपरिहार्य है। परन्तु प्रशिक्षण में प्रतिभागी प्रायः खानापूर्ति करते है। प्रशिक्षण को गम्भीरता से न लेना उनका स्वभाव बन गया है।

10. एक ओर व्यावसायिक बैंकों का मितव्ययता एवं कुशलता के नाम पर एकीकरण किया जा रहा है दूसरी ओर केवल संख्या वृद्धि के लिये समितियों का विखण्डन कर नई समितियाँ बनाई जा रही है।

चूँकि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हमारे सामने है अतः हमें तत्काल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को सक्रिय एवं गतिशील बनाना होगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में सहकारिता का महत्व असंदिग्ध है। हमें सहकारी क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों एवं अकुशलताओं को स्पष्टतः स्वीकार कर इनका शीघ्र निराकरण ह्य करना ही होगा। कमजोरियों पर परदा डालने की नीति त्याग कर हमें समयबद्ध तरीके से सहकारिता के उद्धार के लिये प्रयत्न करना है। सहकारिता की सफलता के लिये स्क्वाड्ढ का मंत्र बहुत उपयोगी है।

S-Self Reliance(आत्म निर्भरता)
Q-Quality Performance (गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन)
U -Unshakable Cooperative Values (अडिग सहकारी मूल्य)
A- Accuntability (जवाबदेही)
D- Develàæpment through modern Techniques (आधुनिक तकनीक से विकास)

सहकारिता की सफलता SQUAD में निहित है। विकसित भारत की प्राप्ति के लिये कृषि एवं सम्बन्धित कषत्रं में नवाचारपूर्ण रूपान्तरण सहकारिता के माध्यम से ही लाया जा सकता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण को मात्र औपचारिकता न मानकर अधिक सार्थक व्यवस्था अपनाना चाहिये। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों एवं संचालकों की प्रशिक्षणोपरांत मूल्यांकन की व्यवस्था की जानी चाहिये।

नवाचार को अपनाने और आत्मनिर्भरता के प्रयत्न करने वाली समितियों को पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई जा सकती है। नई सहकारिता नीति 2025 के अनुसार सहकारी समितियों में समयबद्ध चुनाव हेतु आवश्यक व्यवस्था , की जानी चाहिये। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सहकारी ग्राम की स्थापना अन्य गांवों के लिये बहुत प्रेरक होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है सहकारिता : डा. दीक्षित

■ कोलियारी में सहकारी सदस्यों और किसानों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

धमतरी। जिला सहकारी संघ धमतरी द्वारा कुरूद विकासखंड के नवीन पैक्स कोलियारी में सहकारी सदस्यों व कृषकों का एकदिवसीय सहकारी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन पैक्स परिसर कोलियारी में 7 अगस्त 2026 को कांशीराम साहू पूर्व अध्यक्ष पैक्स भखारा, पूर्व संचालक पैक्स भखारा के बिसौहा राम साहू, देवेंद्र ध्रुव, संतलाल साहू, पैक्स कोलियारी के प्राधिकृत अधिकारी भुनेश्वर नेताम, सफल कृषक ग्राम भेंडसर छबिलाल सिन्हा, प्रवक्ता डॉक्टर एएन दीक्षित, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोलियारी शातिस्वरूप की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

सहकारिता व्यवसायिक संगठन का एक रूप : डा. दीक्षित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि, सहकारिता व्यवसायिक संगठन का एक रूप है। यह एक आर्थिक गतिविधि होने के साथ एक सामाजिक, नैतिक अनुष्ठान भी है। यह ऐसा व्यावसायिक मॉडल है जिसे उपयोगकर्ता स्वामित्व वाला होता है, जबकि अन्य व्यावसायिक मॉडल निवेशक स्वामित्व वाले होते हैं। यह सहकारिता की अनूठी विशेषता है, जो इसे पूंजीवाद के शोषण और समाजवाद की गुलामी से दूर रखती है। वस्तुतः लोकतंत्र और सहकारिता को सच्चा मित्र कहा जा सकता है।

भारत के विकास में सहकारिता का होगा महत्वपूर्ण स्थान

वर्तमान सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता को एक महत्वपूर्ण सोपान माना है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान है तथा ग्रामों का समुचित विकास ही विकसित भारत की राह खोल सकता है। सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। प्राथमिक सहकारी समितियों को ग्रामीण जीवन की धुरी बनाने के लिए सरकार द्वारा इसके नियमों एवं नीतियों में व्यापक सुधार किये जा रहे हैं। इन्हें एकल उद्देश्य से बहुद्देशीय बनाया गया है। नवीनतम डिजिटल तकनीक से जोड़ा गया है तथा ग्राम विकास के नए दायित्वों को निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

सदस्यों की सक्रियता से सफलता तय होती है

सहकारिता चूंकि उपयोगकर्ता स्वामित्व वाले व्यवसाय होते है अतः इनके संचालन एवं सफलता में सदस्यों की सक्रियता का अहम स्थान होता है। किसी समिति के सदस्य जितने अधिक जागरूक एवं सक्रिय होंगे, उस समिति की सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। समिति की बैठकों एवं आम सभाओ में गांव के युवकों को गंभीर भागीदारी करनी चाहिए तथा समिति संचालकों एवं प्रबंधकों को नवाचारों को अपनाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि सहकारी समिति कोई सरकारी विभाग नहीं है। यह आपकी अपनी व्यावसायिक संस्था है, जिसका संचालन भी ग्राम वासियों को ही करना है।

रोपे गए 150 पौधे

कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथियों व ग्रामीण जनों ने प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत अभियान के मूल उद्देश्य देश में वृक्षों की संख्या बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जनमानस में पौधारोपण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पैक्स परिसर में 150 पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कृषक व सहकारी क्षेत्र से जुड़े सदस्य व विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता एवं आभार प्रदर्शन पैक्स कोलियारी के प्रबंधक तरुण साहू ने किया।

सहकारिता से पूर्ण हो सकते हैं हमारे सभी काम

कार्यक्रम में शांति स्वरूप ने अपने उद्बोधन में कहा कि, सहकारिता से हमारे सभी काम पूर्ण हो सकते हैं। केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। देवेंद्र ध्रुव ने कहा कि हमें प्रशिक्षण में दी जाने वाली जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। काशीराम साहू ने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला सहकारी संघ धन्यवाद का पात्र है। संतराम साहू ने कहा कि आयोजको को बहुत-बहुत धन्यवाद, पौधारोपण एवं उसका संरक्षण आज की आवश्यकता है। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया।

कृषि मंत्री नेताम ने छात्रों को दिया 'सहकार से रोजगार' का मंत्र

■ सहकारिता से युवाओं को रोजगार के अवसर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोडने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम ने विद्यार्थियों को 'सहकार से रोजगार' का मंत्र दिया। कृषि महाविद्यालय रायपुर के सेमिनार हॉल में भारतीय श्रम समिति नई दिल्ली, भारतीय गुणवत्ता परिषद एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्याशाला में श्री नेताम ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधियों का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का प्रभावी रास्ता भी है।

कृषि मंत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में युवाओं को केवल नौकरी की तलाश करने के बजाय रोजगार सृजक बनने की दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से युवा मिलकर संसाधनों, तकनीक और बाजार का बेहतर उपयोग कर छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि, दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी ज्ञान और नवाचार को सहकारिता से जोडक़र स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति दी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में सहकारी क्षेत्र में गठित महिला स्व-सहायता समूह तथा किसान उत्पादक संगठन इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने छात्रों से आह्वान किया कि वे सहकारिता की भावना को समझें, टीम के रूप में कार्य करें और स्थानीय संसाधनों को स्थानीय रोजगार में बदलने का प्रयास करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की।

युवाओं को सहकारिता के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु आयोजित इस एक दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यशाला में भारतीय श्रम समिति, नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री लखन लाल साहू, जिला सहकारी बैंक, रायपुर के अध्यक्ष श्री निरंजन सिन्हा, राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री सौरभ शर्मा, जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह एवं सहकारी संघ नई दिल्ली के संचालक सदस्य श्री शिव श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सहकारिता से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के भी पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सहकारिता, रोजगार और उद्यमिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। कृषि महाविद्यालय रायपुर की अधिष्ठाता डॉ. आरती गुहे ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.एस. टूटेजा, विभिन्न विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सहकारी समितियां बनेंगी ग्रामीण सेवाओं का मजबूत केंद्र

■ सचिव सी.आर. प्रसन्ना ने कोतरा पैक्स का निरीक्षण कर किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य सरकार सहकारिता व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग के सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना ने रायगढ़ जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) कोतरा का औचक निरीक्षण किया और किसानों को दी जा रही सुविधाओं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की समीक्षा की।

पैक्स बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित

रायगढ़ जिले के निरीक्षण के दौरान श्री प्रसन्ना ने समिति के रिकॉर्ड, भंडारण व्यवस्था, किसानों को मिल रही सेवाओं और सहकारी गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पैक्स को केवल ऋण वितरण तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि किसानों को कृषि से जुड़ी अधिकतर सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकें।

किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर

सचिव श्री प्रसन्ना ने वीबी–जीराम जी योजना के तहत उपार्जन केंद्रों में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए पक्के चबूतरों के निर्माण के निर्देश संबंधितों को दिया। साथ ही नेफेड के माध्यम से दलहन और तिलहन की खरीदी में सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सचिव श्री प्रसन्ना ने कहा कि, राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सहकारी समितियों को ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन और किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अन्न भंडारण योजना से किसानों को मिलेगा लाभ

सचिव श्री प्रसन्ना ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत रायगढ़ जिले में बन रहे तीन गोदामों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक गोदाम बनने से किसानों की उपज सुरक्षित रहेगी और उन्हें बेहतर कीमत मिलने में मदद मिलेगी।

समितियों में बढ़ेंगी आयवर्धक गतिविधियां

श्री प्रसन्ना ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) की योजनाओं के माध्यम से कृषि अधोसंरचना, भंडारण, विपणन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों का विस्तार करने के निर्देश दिए। सभी पैक्स को मल्टी-पर्पज पैक्स के रूप में विकसित कर कृषि आदान वितरण, उपभोक्ता सेवाएं और अन्य जनोपयोगी सेवाओं का केंद्र बनाने पर भी जोर दिया।

गांवों में ही मिलेंगी डिजिटल और शासकीय सेवाएं

सचिव श्री प्रसन्ना ने पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सभी सेवाएं शुरू करने और समिति को जल्द ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीण नागरिकों को प्रमाण-पत्र और अन्य ऑनलाइन शासकीय सेवाएं अपने गांव के पास ही मिल सकेंगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की त्रैमासिक समीक्षा

रायपुर। सहकारिता क्षेत्र को अधिक सक्षम, दक्ष और परिणामोन्मुख बनाने के लिए सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

संघ मुख्यालय में 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित त्रैमासिक समीक्षा बैठक में वर्ष 2026-27 के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रथम तिमाही की प्रगति एवं लक्ष्य-पूर्ति की समीक्षा की गई। बैठक में अप्रैल से जून 2026 के दौरान आयोजित एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के नेतृत्व विकास और क्षमता विकास को प्रशिक्षण गतिविधियों का प्रमुख आधार बताया गया। अप्रैल माह में प्राथमिक सहकारी सेवा समितियों के प्रबंधकों/कर्मचारियों, पदाधिकारियों तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे।

जिला संघों के सहयोग से व्यापक होगा प्रशिक्षण नेटवर्क

त्रैमासिक समीक्षा बैठक में जिला सहकारी संघों द्वारा पृथक रूप से आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार संबंधित जिला संघों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है तथा जिला संघों द्वारा भी पृथक रूप से प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रशिक्षण से मजबूत होंगी सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता : सौरभ शर्मा– छग राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा ने कहा कि सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना नहीं, बल्कि सहकारी संस्थाओं में कुशल प्रबंधन, बेहतर कार्यप्रणाली और संस्थागत क्षमता का विकास करना है। मई माह में भी पैक्स के पदाधिकारियों, प्रबंधकों एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें कुल 120 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जून माह के लिए बिलासपुर से संबद्ध सहकारी समितियों के लिपिकीय कर्मचारियों तथा पैक्स के पदाधिकारियों एवं प्रबंधकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किए गए।

ये रहे मौजूद

बैठक में राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी ध्रुव, विभिन्न जिला सहकारी संघों से आये अधिकारीगण एवं संघ के कर्मचारी गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सहकारिता बनेगी छत्तीसगढ़ की नई आर्थिक शक्ति : डॉ. सौरव निर्वाणी

■ राज्य सहकारी संघ कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा से

■ सौजन्य भेंट, सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा

बेमेतरा। केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव के छत्तीसगढ़ राज्य सलाहकार नियुक्त होने के उपरांत डॉ. सौरव निर्वाणी ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के राज्य कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर डॉ. निर्वाणी ने सौरभ शर्मा को शॉल पहनाकर सम्मानित किया तथा छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प को साझा किया।

विभिन्न पहलुओं पर हुई चर्चा

सौजन्य भेंट के दौरान छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार एवं सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, विपणन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण तथा ग्रामीण आजीविका से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन, बाजार उपलब्धता एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया।

सहकारिता जागरूकता अभियान चलाने पर बनी सहमति

चर्चा के दौरान प्रदेशभर में सहकारिता जागरूकता अभियान चलाने, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन, संग्रहण एवं प्रसंस्करण के लिए आधुनिक मॉडल विकसित करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल किए जाने पर भी सहमति बनी। संघ के प्राधिकृत अधिकारी सौरभ शर्मा ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं का व्यापक नेटवर्क है और इसे आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन तथा बाजार से जोड़कर ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वरोजगार के अवसर बनेंगे : डॉ. निर्वाणी

डॉ. निर्वाणी ने कहा कि, सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के विजन को छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।

हाजीपल्ली की भगत सिंह थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी पहुंचे प्राधिकृत अधिकारी

■ सहकारी संस्था के पदाधिकारियों से चर्चा कर संस्था की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की ली जानकारी

हैदराबाद। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी ने हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित हाजीपल्ली गांव की भगत सिंह थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने सोसायटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से मुलाकात कर संस्था की कार्यप्रणाली एवं संचालित गतिविधियों की जानकारी ली।

सोसायटी के पदाधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधि प्राधिकृत अधिकारी से चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान संस्था के संचालन, सदस्यों से जुड़ी गतिविधियों तथा सोसायटी द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी का आदान-प्रदान हुआ।

स्थानीय स्तर पर सहकारिता की भूमिका का किया अवलोकन

प्राधिकृत अधिकारी ने स्थानीय स्तर पर संचालित थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सहकारी संस्था की कार्यप्रणाली को समझते हुए सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्था की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सहकारी संस्था के पदाधिकारियों से संस्था के अनुभवों एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की।

संस्थाओं का अध्ययन छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के लिए लाभकारी

उन्होंने कहा कि, गांव स्तर पर संचालित बचत एवं ऋण सहकारी संस्थाएं स्थानीय लोगों को संगठित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी संस्थाओं के सफल अनुभवों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ की सहकारी संस्थाओं को और अधिक सक्षम एवं सदस्य-केंद्रित बनाने की दिशा में उपयोगी पहल की जा सकती है। भ्रमण के दौरान सोसायटी के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

जिला सहकारी संघ महासमुंद में देश की अखंडता का लिया गया संकल्प

महासमुंद। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला सहकारी संघ मर्यादित, महासमुंद के कार्यालय परिसर में संघ के अध्यक्ष श्री गुरुवंश सिंह चावला ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने राष्ट्रगान के साथ देश की एकता, अखंडता एवं समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चावला ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों एवं अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान सपूतों के संघर्ष की याद दिलाता है, जिनके बलिदान के फलस्वरूप आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सामूहिक सहभागिता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास की मजबूत आधारशिला है। सभी को सहकारिता की भावना को और मजबूत करते हुए समाज एवं राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए।

शादनगर की श्री राम सहकार संगम सोसायटी की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए प्राधिकृत अधिकारी

■ सौरभ शर्मा ने 32 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाली सहकारी संस्था की गतिविधियों एवं व्यवसाय मॉडल की ली जानकारी

हैदराबाद। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ दास शर्मा ने हैदराबाद से लगभग 53 किलोमीटर दूर शादनगर स्थित श्री राम सहकार संगम सोसायटी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संस्था की कार्यप्रणाली, विभिन्न सहकारी गतिविधियों एवं व्यवसायिक संचालन की जानकारी ली।

श्री राम सहकार संगम सोसायटी की नेटवर्थ लगभग 32 करोड़ रुपये बताई गई। प्राधिकृत अधिकारी ने संस्था के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा कर यह समझने का प्रयास किया कि सहकारी संस्था द्वारा किस प्रकार विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया है। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था, सदस्य हित में संचालित गतिविधियों, आय के स्रोत तथा सहकारी व्यवसाय के विस्तार से संबंधित विषयों पर जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने संस्था की कार्यप्रणाली एवं सफल व्यवसाय मॉडल का अध्ययन करते हुए छत्तीसगढ़ की सहकारी संस्थाओं में भी ऐसी प्रभावी गतिविधियों को अपनाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

सहकारी संस्थाओं के लिए उपयोगी मॉडल

प्राधिकृत अधिकारी ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को केवल पारंपरिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर उन्हें व्यवसायोन्मुख, आत्मनिर्भर एवं सदस्य-केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है। मजबूत वित्तीय आधार, बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से सहकारी संस्थाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि, देश के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ की सहकारी संस्थाओं में उपयोगी एवं व्यवहारिक मॉडल लागू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे सहकारी संस्थाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ सदस्यों को बेहतर आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

सहकार से समृद्धि के लिए सहकारी शिक्षा जरूरी

सोनारपाल लैम्पस अंतर्गत ग्राम देवड़ा में सहकारी प्रशिक्षण संपन्न

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था इफको के सहयोग से बस्तर विकासखंड के सोनारपाल लैम्पस अंतर्गत ग्राम पंचायत देवड़ा में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में लैम्पस से जुड़े कृषकों एवं सहकारी बंधुओं ने सहभागिता की।

प्रशिक्षण के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के संभागीय कार्यालय, जगदलपुर में पदस्थ वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे ने 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामों के समग्र विकास के लिए सहकारी संस्थाओं का निर्माण बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने आगामी दो वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लैम्पस/पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य पालन जैसी सहकारी समितियों के गठन की संभावनाओं तथा भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

श्री पांडे ने ग्रामीण स्तर पर गठित लैम्पस द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के साथ-साथ कृषक उत्पादक संगठन (FPO) के गठन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को सहकारी संस्थाओं से जुड़कर सामूहिक रूप से अपनी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

इफको अधिकारियों ने दी नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी की जानकारी प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था इफको के बस्तर क्षेत्रीय अधिकारी श्री लाल बहादुर सिंह एवं सहायक फील्ड असिस्टेंट श्री वैभव पांडे ने किसानों को इफको के सामाजिक सरोकारों तथा विभिन्न रासायनिक एवं जैविक कृषि उत्पादों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग, लाभ एवं कृषि में इनके प्रभावी प्रयोग की जानकारी किसानों के साथ साझा की।

इसके साथ ही इफको से खाद की खरीदी पर मिलने वाले 'संकट हरण बीमा' के संबंध में भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई।

किसान क्रेडिट कार्ड एवं ऋण वितरण की जानकारी

लैम्पस सोनारपाल के प्रबंधक श्री प्रेमनाथ वेद ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत ऋण वितरण व्यवस्था एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सोनारपाल लैम्पस के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ संघ के श्री रोमांचल पाणिग्राही का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

जिला सहकारी संघ राजनांदगांव में हुआ ध्वजारोहण

राजनांदगांव। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी संघ मर्यादित, राजनांदगांव के प्रांगण में गरिमामय वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित अतिथियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया तथा देश की एकता, अखंडता एवं समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर श्रीमती रेखा दिनेश साहू, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, भा. तै.सा., नई दिल्ली, श्री एन.एल. टंडन, उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, श्री अमलेंदु हाजरा, पूर्व लोकपाल एवं सहकारी कार्यकर्ता; श्री शैलेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त सह-निदेशक, ग्रामोद्योग, श्री आलोक सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिला सहकारी संघ राजनांदगांव, श्री कृष्ण कुमार चंद्रवंशी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता; श्रीमती अनिता नंदे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़, श्रीमती रश्मि सोनी, सहकारी निरीक्षक तथा श्री एन. कुमार साहू, प्रभारी प्रबंधक, जिला सहकारी संघ राजनांदगांव सहित सहकारिता विभाग के श्री प्रधान एवं श्रीमती गीता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं तथा सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीणों एवं आमजन के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

जिला सहकारी संघ बालोद की 12 वीं वार्षिक आमसभा संपन्न

लेखा-पत्रकों, वार्षिक प्रतिवेदन एवं आगामी बजट पर हुई विस्तृत चर्चा

बालोद। जिला सहकारी संघ मर्यादित बालोद की 12वीं वार्षिक आमसभा का आयोजन 14 अगस्त 2026 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, शाखा बालोद के सभागार में किया गया। आमसभा का शुभारंभ भारत माता के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सहकारी संघ मर्यादित बालोद के प्राधिकृत अधिकारी श्री उमाशंकर शर्मा ने की।

आमसभा में सहकारी वर्ष 2025-26 के लेखा-पत्रकों, वार्षिक प्रतिवेदन तथा सहकारी वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही वार्षिक प्रचार-प्रसार, प्रकाशन एवं अंकेक्षण से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक नीतिगत निर्णय लिए गए। गत वार्षिक साधारण सभा से लेकर वर्तमान आमसभा तक संघ द्वारा किए गए कार्यों एवं गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसका सदस्यों ने अनुमोदन किया।

सहकारी संस्थाओं के हित में सुझाव

आमसभा में राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री झुमुकलाल गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बालोद के नोडल अधिकारी श्री सी.आर. रावटे, शाखा प्रबंधक श्री रोहित आलेन्द्र, सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोण्डी के प्राधिकृत अधिकारी श्री चमन लाल साहू, विपणन सहकारी समिति के प्रबंधक श्री शिवभूषण पटेल तथा प्राथमिक लघुवनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री लोचनराम सिन्हा ने संघ एवं संबद्ध सहकारी समितियों के हित में अपने विचार एवं सुझाव रखे।

अंशदान, ऑडिट और निर्वाचन समय पर कराने पर जोर

जिला सहकारी संघ मर्यादित बालोद के प्राधिकृत अधिकारी श्री उमाशंकर शर्मा ने सभी सहकारी समितियों से संघ का अंशदान समय पर जमा करने तथा समितियों का अंकेक्षण एवं निर्वाचन निर्धारित समय-सीमा में कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं की सक्रियता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध कार्यप्रणाली से ही सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

विभिन्न समितियों के प्रतिनिधि रहे उपस्थित

आमसभा में राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री झुमुकलाल गुप्ता, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बालोद के नोडल अधिकारी श्री सी.आर. रावटे, सहायक नोडल अधिकारी श्री हेमंत पटेल, शाखा प्रबंधक श्री रोहित आलेन्द्र, लिपिक श्री ईश्वर सिंह भुआर्य, विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी, जिला सहकारी संघ की प्रबंधक श्रीमती स्नेहलता साहू, लेखापाल श्री वेदप्रकाश साहू, श्रीमती परमेश्वरी साहू सहित बालोद जिले के पांचों ब्लॉक से मत्स्य, वनोपज, बुनकर, दुग्ध एवं उपभोक्ता भंडार सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

राज्य सहकारी संघ में सौरभ शर्मा ने फहराया तिरंगा

रायपुर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, रायपुर परिसर में गरिमामय वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इसके पश्चात उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्रगान का सामूहिक गायन कर राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इस अवसर पर संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी ध्रुव, जिला सहकारी संघ की प्रबंधक श्रीमती मंजूषा तिवारी सहित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ, जिला सहकारी संघ के अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अपेक्स बैंक मुख्यालय में हर्षोल्लास से मनाया स्वतंत्रता दिवस

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) मुख्यालय, नवा रायपुर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैंक मुख्यालय परिसर में बैंक के प्रबंध संचालक एवं अपर आयुक्त सहकारिता श्री के.एन. कांडे ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में प्रबंध संचालक एवं अपर आयुक्त सहकारिता श्री के.एन. कांडे, अवर सचिव, सहकारिता श्री देवलाल भारती, संयुक्त आयुक्त श्री सुशील तिग्गा, संयुक्त आयुक्त श्री मुकेश ध्रुव, उपायुक्त श्री एन.आर.के. चंद्रवंशी, अपेक्स बैंक डीजीएम श्री भूपेश चंद्रवंशी, एजीएम श्री अरुण पुरोहित, एजीएम श्री एल.के. चौधरी, प्रबंधक श्री ए.के. लहरे, प्रबंधक श्री गुंजार सिंह ठाकुर, प्रबंधक श्री अभिषेक तिवारी सहित बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में दिखी तिरंगे की शान

अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने किया ध्वजारोहण, बैंक परिसर में रोपे गए पौधे

जगदलपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर का परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। बैंक परिसर में आयोजित गरिमामय समारोह में बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बैंक परिसर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंवर सिंह ध्रुव, अतिरिक्त प्रबंधक श्री एस.ए. रज़ा, पर्यवेक्षक श्री मनोज सिंह, श्री संजय पाण्डे सहित बैंक के पदाधिकारी एवं

सहकारी बैंक दुर्ग में प्रीतपाल बेलचंदन ने किया ध्वजारोहण

दुर्ग। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बैंक के अध्यक्ष श्री प्रीतपाल बेलचंदन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर `वर्ग-1 अधिकारी श्री एस.के. निवसरकर, श्री ह्रदेश शर्मा, सुश्री कुसुम ठाकुर, श्री रोहित कुमार वर्मा, कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्री एस.पी. अग्रवाल तथा विधि सलाहकार श्री सुधीर तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन श्री धीरेन्द्र देवांगन ने किया। इस अवसर पर श्री के.के. नायक, अधीक्षक श्री एस.पी. वाहने, ए.एस. खान, रामकुमार वर्मा, आर.के. मोहनमाला, चंद्रशेखर मानिकपुरी सहित प्रधान कार्यालय दुर्ग एवं शाखा दुर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

संभागीय कार्यालय जगदलपुर में फहराया गया तिरंगा

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित के संभागीय कार्यालय जगदलपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दलपत सागर वार्ड के पार्षद एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित जगदलपुर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरसिंह राव ने ध्वजारोहण किया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री विवेकानंद झा, प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे, श्री मितेश पाणिग्राही, लिपिक श्री किशोरी लाल ठाकुर सहित संभागीय कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया।

देशप्रेम से ओत-प्रोत रहा कार्यक्रम

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्य शाखा बिलासपुर में ध्वजारोहण के साथ वंदे मातरम् का हुआ गायन

बिलासपुर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर की मुख्य शाखा में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी रजनीश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला सहकारी संघ रायपुर में शान से लहराया तिरंगा आयोजन

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिला सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के कार्यालय परिसर में प्राधिकृत अधिकारी श्री पी.सी. ध्रुव ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर संघ के प्राधिकृत अधिकारी श्री सौरभ शर्मा, प्रबंध संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंह, जिला सहकारी संघ की प्रबंधक श्रीमती मंजूषा तिवारी सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, चौबे कॉलोनी रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ एवं जिला सहकारी संघ के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सिन्हा ने किया ध्वजारोहण

रायपुर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर में बैंक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रध्वज को नमन किया।

समारोह में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी गरिमामय रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रभक्ति के साथ जनसेवा, वित्तीय समावेशन और सहकारिता के माध्यम से समाज के आर्थिक विकास में योगदान देने का संकल्प दोहराया गया।

बालोद जिला सहकारी संघ में फहराया गया तिरंगा

बालोद। स्वतंत्रता दिवस पर जिला सहकारी संघ मर्यादित, बालोद के कार्यालय परिसर में प्राधिकृत अधिकारी श्री उमाशंकर शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में संघ बालोद के प्राधिकृत अधिकारी एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री उमाशंकर शर्मा, सहकारी निरीक्षक श्री मनोज नेताम, श्री भूपेंद्र मंडावी, श्री सेवंत कुमार साहू, जिला सहकारी संघ की प्रबंधक श्रीमती स्नेहलता साहू, संघ के लेखापाल श्री वेदप्रकाश साहू, श्रीमती मंगला साहू, श्रीमती प्रीति साहू, उमाशंकर सवार, श्रीमती संतोषी बाई साहू एवं श्रीमती परमेश्वरी साहू सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जिला सहकारी संघ धमतरी में हुआ ध्वजारोहण

धमतरी। जिला सहकारी संघ मर्यादित, धमतरी में श्री शगुन पटेल ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर गोकुलधाम कॉलोनी के श्री मांगीलाल राठी, प्रकाश वाशानी, सुरेश राठौड़, बजरंग अग्रवाल, शोभा राठौर, सुरभि रघाटाटे, रेखा मेहता, विनीत राठौर, राधेश्याम चंद्राकर, सुरेश मेहता, विक्की रघाटाटे, ओम लता पटेल, निखिल रघाटाटे, हिमेश मेहता, लता रघाटाटे सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक विवेकानंद झा द्वारा क्वालिटी आफसेट, पुरानी बस्ती, रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाइट www.cgcoop.in E-mail : cgcoopnews@gmail.com